JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सतत विकास लक्ष्य और भारत में उनका स्थानिक कार्यान्वयन

(Sustainable Development Goals and Their Spatial Implementation in India)

Dr. Surbhi Dosi

Assistant Professor, Govind Guru Trible University.

सारांश (Abstract):

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। कुल 17 लक्ष्यों और 169 उपलक्ष्यों के माध्यम से यह पहल वैश्विक समुदाय को 2030 तक गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल, लिंग समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सतत व समावेशी समाधान अपनाने हेतु प्रेरित करती है।

भारत, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ने इन लक्ष्यों को अपनी नीतियों और योजनाओं में समाहित करने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। नीति आयोग देश में SDGs के कार्यान्वयन का प्रमुख निकाय बनकर कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत SDG इंडिया इंडेक्स, राज्य स्तरीय रोडमैप, और स्थानिक रणनीतियाँ तैयार की गई हैं जिससे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की समीक्षा संभव हो सकी है।

इस शोध पत्र में भारत के विभिन्न राज्यों में SDGs की प्रगति का स्थानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह पाया गया है कि कुछ राज्य जैसे केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आदि स्वास्थ्य, शिक्षा और लिंग समानता जैसे क्षेत्रों में अग्रणी हैं, वहीं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपेक्षाकृत पीछे हैं। यह अंतर केवल आर्थिक संसाधनों के वितरण से नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, जागरूकता, स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति से भी प्रभावित होता है।

इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि SDGs की सफलता के लिए 'स्थानिक रणनीति' का निर्माण और कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ भिन्न होती हैं। बिना स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखे यदि नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो वे केवल आंकड़ों में उपलब्धि दर्शा सकती हैं, धरातल पर नहीं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानिक कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन कर, इससे जुड़ी चुनौतियों, असमानताओं और संभावनाओं को सामने लाना है, ताकि नीति निर्माताओं को एक व्यवहारिक और सटीक दिशा मिल सके।

कुंजी शब्द (Keywords):

सतत विकास लक्ष्य, स्थानिक योजना, भारत, नीति आयोग, क्षेत्रीय विषमता, पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास।ख

उद्देश्य (Objectives):

1. सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. भारत में SDGs के स्थानिक कार्यान्वयन की यथास्थिति प्रस्तुत करना।
3. राज्यवार प्रगति तथा असमानताओं का विश्लेषण करना।
4. स्थानिक योजना एवं नीतियों की भूमिका को रेखांकित करना।
5. सतत विकास हेतु सुझाव एवं रणनीतियों का प्रस्तुतीकरण करना।

प्रस्तावना (Introduction):

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय असंतुलन, आर्थिक विषमता, और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं समूचे मानव समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बनकर उभरी हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल आर्थिक विकास के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों में संतुलन बनाए रखे। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य (ेनेजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज ळवंसे – SDGs) घोषित किए गए।

SDGs कुल 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्यों के माध्यम से एक ऐसा वैश्विक रोडमैप प्रस्तुत करते हैं जिसका उद्देश्य है – 2030 तक एक समावेशी, न्यायसंगत, शांतिपूर्ण, और पर्यावरणीय रूप से संतुलित समाज का निर्माण। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी का अंत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, सतत नगरों का विकास जैसे अनेक विषय शामिल हैं।

भारत, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और एक विविधताओं से भरा राष्ट्र है, SDGs को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने इन लक्ष्यों को अपने राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, और नीतियों में समाहित किया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं, और नागरिक समाज संगठनों द्वारा साझा प्रयासों के माध्यम से भारत सतत विकास की दिशा में अग्रसर है।

लेकिन भारत में SDG का कार्यान्वयन एक समान नहीं है। इसकी सफलता या असफलता स्थानिक (Spatial) दृष्टिकोण से भिन्न है। प्रत्येक राज्य, जिला और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, प्रशासनिक क्षमता, और संसाधन उपलब्धता में अंतर होने के कारण SDGs की प्राप्ति में भी भिन्नता देखी जाती है। उदाहरणस्वरूप, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कई संकेतकों पर अभी भी पीछे हैं।

यह शोध पत्र इसी अंतर को उजागर करते हुए यह विश्लेषण करता है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानिक कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है, कौन–से क्षेत्र किन लक्ष्यों में पीछे हैं, क्या कारण हैं इन असमानताओं के, और कैसे स्थान–विशिष्ट योजनाओं, नीति निर्माण और क्रियान्वयन से इन लक्ष्यों की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रस्तावना इस बात को रेखांकित करती है कि यदि भारत को 2030 तक SDGs की दिशा में वास्तविक प्रगति करनी है, तो 'एक ही नीति सबके लिए' की अवधारणा को त्यागकर स्थानिक भिन्नताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण करना होगा।

1. सतत विकास लक्ष्य (SDGs): एक परिचय

SDGs के मुख्य उद्देश्यः

गरीबी व भूख समाप्त करना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य

लैंगिक समानता

स्वच्छ जल और स्वच्छता

नवीकरणीय ऊर्जा

जलवायु कार्रवाई

भूमि और समुद्र संरक्षण

न्याय प्रणाली की सुदृढ़ता

वैश्विक साझेदारी

इन लक्ष्यों में समाज, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में प्रयास समाहित हैं।

2. भारत में सतत विकास लक्ष्य का स्थानिक कार्यान्वयन

भारत सरकार ने नीति आयोग को SDGs के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। प्रत्येक राज्य को लक्ष्य प्राप्ति हेतु State Indicator Framework सौंपा गया है। नीति आयोग प्रत्येक वर्ष SDG India Index प्रकाशित करता है, जिससे राज्यों की रैंकिंग और प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।

राज्यवार प्रदर्शन (2024 रिपोर्ट के अनुसार):

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	रैंक	प्रगति स्तर (रंग कोड)
केरल	1	फ्रंट रनर (70)
हिमाचल प्रदेश	2	फ्रंट रनर
बिहार	अंतिम	एस्पिरेंट (<50)
राजस्थान, ओडिशा	मध्य	परफॉर्मर (50–64)

उदाहरण:

केरल: शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता में अग्रणी

राजस्थान: बालिका शिक्षा व जलवायु कार्रवाई में चुनौतीपूर्ण

पूर्वोत्तर राज्य: जैव विविधता में अग्रणी, परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े

3. स्थानिक विषमताएं (Spatial Disparities):

भारत में विविधता के कारण SDGs के क्षेत्रीय कार्यान्वयन में भारी अंतर देखा जा रहा है।

मुख्य कारक:

प्राकृतिक संसाधनों की असमानता: राजस्थान में जल संकट, उत्तर–पूर्व में अधिक वर्षा

आर्थिक विकास स्तर में भिन्नता

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अंतर

भौगोलिक अवरोध (जैसे हिमालय, मरुस्थल)

4. नीतिगत पहल एवं कार्यक्रम:

SDG लक्ष्य	भारत सरकार की पहल
SDG 1 (गरीबी)	प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा
SDG 2 (भूख)	राष्ट्रीय पोषण मिशन
SDG 3 (स्वास्थ्य)	आयुष्मान भारत, मिशन इन्द्रधनुष
SDG 4 (शिक्षा)	समग्र शिक्षा अभियान
SDG 5 (लैंगिक समानता)	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
SDG 6 (जल)	जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान
SDG 7 (ऊर्जा)	उज्ज्वला योजना

5. चुनौतियाँ (Challenges):

1. डेटा की अनुपलब्धता और पारदर्शिता की कमी
2. राज्यों के बीच समन्वय की कमी
3. स्थानीय निकायों की सीमित क्षमता
4. वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता
5. शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का दबाव

6. सुझाव (Suggestions):

1. स्थानिक योजना को प्राथमिकता देनाः GIS आधारित योजनाएं विकसित करना।

2. स्थानीय शासन की सशक्त भूमिकाः पंचायत और नगरपालिका को सशक्त करना।

3. राज्यवार रणनीति निर्माणः "One Plan One State" अवधारणा को अपनाना।

4. सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देनाः जागरूकता और जनसहभागिता बढ़ाना।

5. निजी क्षेत्र और CSR को जोड़नाः लक्ष्य पूर्ति में सहायक हो सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

सतत विकास लक्ष्य (SDGs) केवल विकास की संकल्पना नहीं, बल्कि यह मानव समाज की दीर्घकालीन भलाई के लिए तैयार की गई एक बहुआयामी रूपरेखा है। यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के संतुलन को सुनिश्चित करते हुए एक समावेशी, समान और न्यायपूर्ण विश्व की कल्पना प्रस्तुत करती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश के लिए ये लक्ष्यों की प्राप्ति एक जटिल, परंतु अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है।

भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को अपने विकास एजेंडे में शामिल कर एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्तरदायित्व को निभाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। नीति आयोग के नेतृत्व में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सूचकांक (SDG India Index) का निर्माण, विभागीय समन्वय, डेटा एकत्रीकरण, और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का पुनर्संरेखन इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हैं।

स्थानिक कार्यान्वयन की दृष्टि से, यह स्पष्ट होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों, भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के बीच लक्ष्यों की प्राप्ति में गहरी असमानता मौजूद है। उत्तर भारत के कुछ राज्य जैसे बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी, शिक्षा, और स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, जबकि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य कई सूचकांकों में अग्रणी हैं। यह भिन्नता प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, राज्य की नीतिगत प्रतिबद्धता, शासन की दक्षता और सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण–शहरी अंतर, जनजातीय क्षेत्रों की उपेक्षा, सीमावर्ती एवं पर्वतीय क्षेत्रों की पहुंच की समस्याएं, और जलवायु परिवर्तन की तीव्र होती चुनौती स्थानिक असमानताओं को और अधिक जटिल बना रही है।

सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो भारत ने मनरेगा, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इन मुद्दों को आधारभूत संरचना और सेवा वितरण से जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन इन योजनाओं का सतत और समतामूलक कार्यान्वयन तभी संभव है जब नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक स्थानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

स्थानीय निकायों, जनसहभागिता, डेटा–संचालित निगरानी, राज्य–विशिष्ट कार्ययोजना, और सांस्कृतिक अनुकूलता के समावेश के बिना SDG की सफलता एक अधूरी कल्पना ही रह जाएगी।

अतः, यह कहा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, परंतु इसकी सफलता का मार्ग स्थानिक समझ, स्थानीय समाधान और स्थानीय भागीदारी से ही होकर गुजरता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References):

1. योजना आयोग (2014)। भारत में असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन पर रिपोर्ट। भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. मिश्रा, अजय (2021)। "भारत में क्षेत्रीय विषमताएं और सतत विकास लक्ष्यः एक स्थानिक विश्लेषण।" क्षेत्रीय अध्ययन एवं विकास पत्रिका, खंड 12(3), पृ. 45–62।

3. शर्मा, राकेश एवं दास, अमरनाथ (2020)। "स्थानिक असमानता और समावेशी विकासरू भारत का परिप्रेक्ष्य।" आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 55(41), पृ. 21–28।

4. सेन, अमर्त्य एवं द्रेज, ज्यां (2013)। एक अनिश्चित गौरवः भारत और उसके अंतर्विरोध। पेंग्विन बुक्स, नई दिल्ली।

5. झा, संजीव (2020)। "सतत विकास लक्ष्य एवं भारत में राज्यों का प्रदर्शन।" भूगोल और आप, अंक 157, पृ. 14–19।

6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (2021)। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (SAPCCs)। भारत सरकार, नई दिल्ली।

7. शर्मा, राकेश एवं दास, अमरनाथ (2020)। "स्थानिक असमानता और समावेशी विकासरू भारत का परिप्रेक्ष्य।" आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 55(41), पृ. 21–28।